भरतपुर रेल टर्मिनल के लिए उपयुक्त स्थान का चयन जल्दी करें-मुख्यमंत्री

उत्तर-पश्चिम रेलवे अधिकारियों को रतलाम-डूंगरपुर परियोजना की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज करने के निर्देश

जयपुर, 9 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान में रेलवे नेटवर्क का सुदृढ़ ीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य में रेलवे परियोजनाओं के विस्तार से न केवल आवागमन सुविधाजनक होगा, बल्कि स्थानीय उद्योग, कृषि और रोजगार को भी नई ऊर्जा मिलेगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय में मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में शर्मा ने रतलाम-डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा नई रेल परियोजना और भरतपुर में प्रस्तावित नवीन रेल टर्मिनल की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि भरतपुर रेल टर्मिनल के निर्माण से किसानों, व्यापारियों और औद्योगिक इकाइयों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि टर्मिनल के लिए उपयुक्त स्थल का चयन संयुक्त निरीक्षण के आधार पर जल्द किया जाए, जिससे परियोजना की गति प्रभावित न हो।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को रतलाम-डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा नई रेल परियोजना और भरतपुर में प्रस्तावित नवीन रेल टर्मिनल प्रगति की समीक्षा की।

शर्मा ने उत्तर-पश्चिम रेलवे के अधिकारियों से रतलाम-डूंगरपुर परियोजना की वस्तुस्थिति पर विस्तृत जानकारी ली और भूमि अधिग्रहण की

■ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंगलवार को सीएमओ में दोनों परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की।

प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग पर भी विशेष जोर देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह संकल्पित है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित, राज्य सरकार और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में संबंधित जिलों के कलेक्टर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

नेपाल में जन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अब नेपाल की सेना इस बेकाबू हिंसा को रोकने और किसी वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है। यह जनविरोध अचानक भले ही प्रतीत होता हो, लेकिन यह वर्षों से बनते आ रहे असंतोष का विस्फोट है, जिसकी जड़ें नेपाल के राजा और उनके परिवार की सामूहिक हत्या और उसके बाद की अव्यवस्था में हैं।

देश में समय-समय पर विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन युवा पीढ़ी सत्ता के लिए हो रही परिवारवादी राजनीति और भ्रष्टाचार से थक चुकी थी। घटनाओं ने तब करवट ली, जब युवा वर्ग का धैर्य जवाब दे गया। सरकारी नेताओं और उनके परिवारों की स्विट्ज़रलैंड, ब्रिटेन और दुबई में मौज-मस्ती की तस्वीरों ने आग में घी डाल दिया। जैनरेशन ज़ी कहलाने वाली इस युवा पीढ़ी ने सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध शुरू किया, लेकिन सरकार ने इस पर कठोर दमनात्मक कार्रवाई की, जिसमें उन्नीस प्रोफेसरों की मृत्यु हो गई। इससे जनआक्रोश और अधिक उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने हर प्रकार के सरकारी प्रतीकों को निशाना बनाया। सरकारी दफ्तरों को जलाया गया, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्शा गया। मंत्रालयों पर हमला कर उन्हें तोड़ा-फोड़ा गया, और कुछ मामलों में नेताओं को निर्दयता से मार डाला गया। पूर्व राजनीतिक नेताओं से लेकर वर्तमान सरकार के सदस्यों तक, सभी पर हमले हुए हैं,नेपाल की संसद को प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है।

नेपाल के प्र.मंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल के आवास समेत कई मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया, जिनमें मंत्री गुरुङ का घर भी शामिल था। कई कैबिनेट मंत्रियों ने या तो इस्तीफा दे दिया या फिर इस्तीफे की घोषणा की, यह कहते हुए कि सरकार प्रदर्शनकारियों की समस्याओं को नज़रअंदाज़ कर रही है। नेपाल कैबिनेट में प्रधानमंत्री सहित कुल 25 मंत्री हैं।

गृह मंत्री रमेश लेखक, जो गठबंधन सरकार में नेपाली कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे, ने सोमवार को हुई हिंसक झड़पों के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। मंगलवार को कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल ने एन.टीवी को बताया कि वे भी इस्तीफा देंगे क्योंकि "ऐसे हालात में सरकार में बने रहना संभव नहीं है।" इसी तरह, युवा एवं खेल मंत्री तेजू लाल चौधरी और जल मंत्री प्रदीप यादव ने भी इस्तीफा दिया। चौधरी ने बताया कि सरकार को युवाओं की समस्याओं की जानकारी थी, लेकिन उसने उन्हें नज़रअंदाज़ किया। सांसद असीम शाह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस नेता शेखर कोइराला ने अपने करीबी मंत्रियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया है। दिन की शुरुआत में काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय ने राजधानी में सुबह 8:30 बजे से अगले आदेश तक कर्फ्यू की घोषणा की थी। काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जिलों में कर्फ्यू लागू किया गया।

शुक्रवार को सरकार के साथ पंजीकरण न कराने के कारण 26 सोशल मीडिया साइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सोमवार को काठमांडू में भारी विरोध प्रदर्शन हुए, जब हजारों युवाओं, जिनमें स्कूली छात्र भी शामिल थे, ने "जैन ज़ी" के बैनर तले संसद के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए, जिसमें तत्काल प्रतिबंध हटाने की मांग की गई।

गोविन्द पारीक मुख्यमंत्री के ओएसडी बने

गोविंद पारीक

जयपुर, 9 सितम्बर (कासं)। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त पूर्व निदेशक डॉ. गोविंद पारीक को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विशेषाधिकारी (ओ.एस.डी.) नियुक्त किया गया है।

■ लम्बे समय तक राजकीय सेवा में रहने के बावजूद वे विवादों से दूर रहे हैं।

ज्ञातव्य है कि गोविंद पारीक ने अपने लंबे कार्यकाल में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं। वे सबसे लंबे समय तक जयपुर के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी रहे। विशेष बात यह रही कि लंबे समय तक राजकीय सेवा देने के बावजूद, वे विवादों से दूर रहे और हर सरकार में उन्हें सम्मानजनक पदों पर कार्य करने का अवसर मिला। पत्रकारों को साथ लेकर चलने और सरकार की नीतियों व योजनाओं का प्रभावी प्रचार-प्रसार करने की उनकी शैली सराही जाती रही है। पारीक दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र में भी लंबे समय तक उद्घोषक के रूप में सक्रिय रहे। डॉ. पारीक ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अलावा, हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी सैकड़ों नवागुंतक पत्रकारों को प्रशिक्षित करने का भी सराहनीय कार्य किया।

एयर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हवाई अड्डे को बंद किये जाने के मद्देनजर काठमांडू के लिए और वहां से आने वाली अपनी सभी उड़ानें फिलहाल निलंबित कर दी हैं। काठमांडू के लिए सेवा देने वाली तीसरी कंपनी स्पाइसजेट ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

एन. डी. ए. के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समिति (बीआरएस) ने भी चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। पार्टी ने कहा कि यह निर्णय राज्य के किसानों की "यूरिया की कमी की पीड़ा" के कारण लिया गया है।

पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने कहा, "पिछले 20 दिनों से बीआरएस राज्य और केन्द्र सरकारों को यूरिया की कमी के बारे में चेतावनी दे रही है। इसके बावजूद उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तेलंगाना के 71 लाख किसानों के साथ एकजुटता दिखाने और उक्त विरोध के रूप में बीआरएस ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। अगर नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प होता, तो हम वही चुनते।"

बीआरएस के पास राज्यसभा में चार सांसद हैं दामोदर राव दिवकोंडा रेड्डी, बी. पार्थसारथी रेड्डी, के.आर. सुरेश रेड्डी, और रवि चंद्र वड्डिराजु। लोकसभा में पार्टी का कोई सांसद नहीं है। शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) ने भी उप-राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लिया। पार्टी ने कहा कि केन्द्र सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से उन्हें राज्य में आई "अभूतपूर्व बाढ़" से निपटने में कोई सहायता नहीं मिली। पार्टी ने 'एक्स' पर लिखा, "पंजाब और पंजाबी हमेशा हर संकट की घड़ी में राष्ट्र के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन आज स्वयं पंजाबी अप्रत्याशित बाढ़ के कारण एक गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। राज्य का लगभग एक-तिहाई हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, घर और फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं।" "न तो राज्य सरकार और न ही केन्द्र सरकार ने किसी भी तरह से पंजाबी जनता की सहायता की है। इस संकट से आम पंजाबी और विशेष रूप से सिक्ख बिना किसी सरकारी मदद के लड़ रहे हैं।" पूर्व केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल एसएसडी की एकमात्र सांसद हैं।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाता मंडल में कुल 788 सदस्य हैं, राज्यसभा के 245 और लोकसभा के 543 सदस्य। राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी मतदान के पात्र हैं।

वर्तमान में, राज्यसभा की 6 सीटें और लोकसभा की 1 सीट रिक्त होने के कारण, कुल 781 सदस्य मतदाता मंडल में शामिल हैं। इस चुनाव में बहुमत का आंकड़ा 391 है। एनडीए के पास लोकसभा में 293 सांसद और राज्यसभा में 129 सदस्य हैं, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन को लगभग 325 सांसदों का समर्थन प्राप्त है।

विपक्ष ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तरह भाजपा को मदद करने के लिए मतदान से अलग रहे।

राहुल गांधी, जो मलेशिया में विदेश दौरे पर थे, समय पर लौट आए और उन्होंने वोट डाला। लोकसभा और राज्यसभा के सभी विपक्षी सांसदों ने भी वोट दिया। भले ही भाजपा ने अपने उम्मीदवार को जिता लिया हो, लेकिन पिछली बार की तुलना में उसके घटते वोट उसकी स्थिति का अलग ही संदेश दे रहे हैं। कई दल भाजपा से दूरी बना रहे हैं और कुछ मजबूरी में उसके साथ बने हुए हैं। तेलुगु देशम पार्टी और भाजपा के बीच गहरे मतभेद की खबरें पार्टी नेताओं ने दी हैं। यह विवाद जल्द ही खुलकर सामने आ सकता है।

ब्लूटूथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बीएस चौहान ने कहा कि आरोपी ने संगठित नकल गिरोह में शामिल होकर परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया है इसलिए उसे जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इन्कार कर दिया है।

पंजाब के लिए 1600 करोड़ रु. की मदद का एलान किया मोदी ने

चंडीगढ़ , 09 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 1,600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित पंजाब में प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। पीएम मोदी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, जो 1988 के बाद से सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है।

पंजाब और उसके पड़ोसी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने हवाई सर्वेक्षण करने के बाद राज्य के सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों में से एक गुरदासपुर पहुंचे। इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने राज्य में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति का जायजा लिया। गुरदासपुर में पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ-साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीम से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिति की समीक्षा के लिए गुरदासपुर में एक आधिकारिक बैठक की अध्यक्षता की। पंजाब में विनाशकारी बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 51 हो गई है। जबकि 1.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। पंजाब सरकार ने राज्य में आई बाढ़ के कारण 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया है।

'धर्म परिवर्तन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सत्ता पक्ष ने निर्दलीय विधायकों के समर्थन से ध्वनिमत से विधेयक पारित करा लिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे जन भावनाओं का सम्मान और समाज की रक्षा का संकल्प करार दिया है। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़ म ने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, खासकर बांसवाड़ा, अलवर जैसे जिलों से। इसलिए सरकार ने कठोर कानून लाकर इस पर निर्णायक कार्रवाई करने का रास्ता चुना है।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों के बाद अब राजस्थान भी उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है, जहां जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कठोर कानूनी प्रावधान प्रभावी रूप से लागू हो चुके हैं।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908